चीन द्वारा वैज्ञानिक शोध में खुलेपन की घोषणा

चीन ने भी वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन में खुलेपन की नीति को समर्थन दिया है। चीन के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान प्रतिष्ठान और चीनी विज्ञान अकादमी ने 15 मई को घोषणा की कि जो शोधकर्ता उनके वित्तीय सहयोग से शोध कार्य करते हैं, उन्हें अपने शोध पत्र को प्रकाशन के 1 साल के अंदर सार्वजनिक दायरे में लाना होगा। गौरतलब है कि उक्त दो संस्थाएं चीन में अधिकांश वैज्ञानिक शोध को वित्तीय सहायता देती हैं।

आजकल दुनिया भर में वैज्ञानिक शोध सम्बंधी प्रकाशनों को सार्वजनिक दायरे में रखे जाने की मुहिम चल रही है। कई देश पहले ही इस आशय की घोषणाएं करके व्यवस्थाएं बना चुके हैं। अन्य देश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मसलन यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पहले ही यह नियम बना दिया है कि उसके पैसे से किए जाने वाले शोध से तैयार हुए शोध पत्रों को 1 वर्ष के अंदर एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी ऑनलाइन शोध पत्रिका में प्रकाशित करना होगा। इसी प्रकार से ब्रिटेन में तो प्रकाशन के दिन से ही शोध पत्र को खुला रखना होगा।

चीन द्वारा लिए गए निर्णय के महत्व को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक शोध पत्रों में उसका योगदान तेज़ी से बढ़ा है। मसलन, साइन्स साइटेशन इंडेक्स के डैटाबेस से पता चलता है कि चीन में 2003 में कुल 48,000 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे जो दुनिया भर में प्रकाशित कुल शोध पत्रों में से 5.6 प्रतिशत थे। तुलना के लिए देखें कि वर्ष 2012 में चीन से 1,86,000 शोध पत्र प्रकाशित हुए जो विश्व के कुल शोध पत्रों में से 13.9 प्रतिशत थे।

चीनी वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित उपरोक्त शोध पत्रों में से 55.2 प्रतिशत के लिए वित्तीय समर्थन राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान प्रतिष्ठान से मिला था। इसके अलावा चीनी विज्ञान अकादमी से जुड़े वैज्ञानिकों ने 18,000 शोध पत्र प्रकाशित किए थे। और ये शोध पत्र सिर्फ वे हैं जो साइंस साइटेशन इंडेक्स में शामिल हुए हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में शोध पत्र अन्य स्थानीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं।

तो चीन की उक्त दो अग्रणी विज्ञान संस्थाओं द्वारा किए गए खुलेपन के निर्णय का व्यापक असर होगा। भारत में भी कृषि अनुसंधान परिषद समेत कई संस्थाओं ने खुलेपन की नीति को अपना लिया है। ***(स्रोत फीचर्स)***